

सिविल मिसेलेनियस

माननीय न्यायालय डी. के. महाजन और पी. सी. पंडित, जे. जे.

एम/एस श्री लक्ष्मी कॉटन ट्रेडर्स पीवीटी लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और,-उत्तरदाता

सिविल रिट नं. 1968 का 311

मई 17, 1968.

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966 का XXXI)-धारा 88 और 89-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 और 301 (ए)-हरियाणा राज्य विधानमंडल-क्या 1 नवंबर, 1966 से पहले की अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति है-ऐसा कानून नए पंजाब राज्य, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और स्थानांतरित क्षेत्रों में कानून के साथ एक ही विषय पर समान नहीं है।- चाहे वह भेदभाव से ग्रस्त हो और अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित हो-पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और वैधता) अधिनियम (VII of 1967) संशोधन अधिनियम-क्या घोषित वस्तुओं पर दोहरे कराधान की परिकल्पना की गई है और इसलिए खराब है- एकल लेवी के लिए एक चरण तय करने वाले अधिनियम में संशोधन-दूसरा लेवी संभव अधिनियम-क्या उस अंक पर निरस्त किया जाना है-अधिनियम की अनुसूची 'डी'-क्या आयातित और स्थानीय कपास के बीच कोई भेदभाव करता है और क्या संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) द्वारा प्रभावित है।

अभिनिर्धारित किया गया कि एक राज्य विधानमंडल ऐसे कानूनों को अधिनियमित करने के लिए स्वतंत्र है जिनका पूर्वव्यापी संचालन होगा। अतीत की एक निश्चित अवधि के लिए कानून बनाने की इसकी क्षमता, इसकी वर्तमान विधायी शक्ति पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि इसके अधिनियमन के लागू होने की अवधि में उसके पास क्या था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 और 89 का तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य विधानमंडल में अपने क्षेत्रों के लिए पूर्वव्यापी कानून बनाने की अंतर्निहित शक्ति को नकार दिया गया था और केवल हरियाणा और पंजाब के नए राज्य को उनके जन्म से ही संभावित रूप से कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। धारा 88 केवल कानूनों की क्षेत्रीय सीमा से संबंधित है और पुरानी पंजाब कानून को नए राज्यों या क्षेत्रों का कानून बनाती है जब तक कि इसे सक्षम विधानमंडलों द्वारा अन्यथा परिवर्तित नहीं किया जाता है। धारा 89 केवल अनुकूलन की शक्ति प्रदान करती है और किसी भी राज्य द्वारा अपने क्षेत्रों के लिए पूर्वव्यापी रूप से कानूनों को पारित करने से मना नहीं करती है। इसलिए हरियाणा राज्य विधानमंडल के पास 1 नवंबर, 1966 से पहले की अवधि के लिए अपने क्षेत्रों के संबंध में पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति है, जब यह अस्तित्व में आया था।

(Para 9, 12 & 17).

माना जाता है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत, पुराने पंजाब राज्य को चार टुकड़ों में विभाजित किया गया है, अर्थात् हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, हस्तांतरित क्षेत्र जो 1 नवंबर, 1966 से हिमाचल प्रदेश और नए राज्य पंजाब में चले गए हैं। हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा 1 नवंबर, 1966 तक की अवधि के लिए अपने क्षेत्रों के संबंध में पारित विधि भेदभाव से ग्रस्त नहीं है, भले ही पुराने पंजाब के क्षेत्रों में, जो हिमाचल प्रदेश

और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में चले गए हैं और नए पंजाब राज्य में इसके समान कोई प्रावधान न हो, जब तक कि हरियाणा के क्षेत्र में विधि समान हो।

(Para 15).

यह माना गया कि पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और वैधता) अधिनियम, 1967 अपने क्षेत्रों के लिए यह नहीं कहता है कि एक ही वस्तु पर दो बार कर लगाया जाए। इसका उद्देश्य केवल एक बार कर लगाना है। लेकिन अगर पंजाब के पुनर्गठन के कारण ऐसा परिणाम सामने आ सकता है, तो यह इसलिए नहीं है कि अधिनियम खराब है, बल्कि इसलिए है क्योंकि एक निश्चित घटना ने हस्तक्षेप किया है, अर्थात्, पंजाब का विभाजन; और यदि एक ही वस्तु पर, 1 नवंबर, 1966 से पहले, दो बार कर लगाया जाता है और यह तथ्य साबित हो जाता है, तो मूल्यांकन किए जाने पर राहत दी जाएगी। केवल यह तथ्य कि एक ही वस्तु पर दो बार कर लगाया जा सकता है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि अधिनियम खराब है।

(Para 18).

जब आयातित कपास हरियाणा राज्य में बेचा जाता है, तो उसके बिक्री मूल्य पर कर लगाया जाएगा। इसी तरह, जब हरियाणा राज्य में पहली बार स्थानीय सामान खरीदा जाता है, तो खरीद मूल्य पर कर लगाया जाएगा जो स्पष्ट रूप से पहला बिक्री मूल्य है। ऐसा होने पर, दोनों प्रकार की वस्तुओं में, हरियाणा राज्य में वस्तुओं के पहले बिक्री मूल्य पर कर लगाया जाना है। इस प्रकार दो प्रकार के कपास के बीच कोई भेदभाव नहीं है और उन पर लगाए गए कर की मात्रा में कोई अंतर नहीं हो सकता है। इसलिए संशोधन अधिनियम की अनुसूची 'डी' संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) से प्रभावित नहीं है।

(Paras 25 and 26).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो उत्तरदाताओं को पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और वैधता) अधिनियम संख्या 14, 1967 और पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम संख्या 14, 1967 और 1956 के केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 74 द्वारा संशोधित 1948 के पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम 46 को किसी भी तरह से प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबंधित करता है और उत्तरदाताओं को 1948 के अधिनियम संख्या 46 के तहत कर के भुगतान को लागू करने और राज्य और केंद्रीय राज्य कर अधिनियम के तहत मूल्यांकन कार्यवाही शुरू नहीं करने का निर्देश देता है।

याचिकाकर्ता के लिए आर. एन. नरूला और सी. डी. गार्ग, अधिवक्ताओं के साथ एच. एल. सिबल, वरिष्ठ अधिवक्ता।

आनंद स्वरूप, अधिवक्ता-जनरल, (हरियाणा) जे. सी. वर्मा, अधिवक्ता और सी. डी. दीवान, प्रत्यर्थियों के लिए -

निर्णय

महाजन जे

- 1) यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका है। इस याचिका में पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) के कुछ प्रावधानों की वैधता और पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और वैधता अधिनियम, 1967 (जिसे इसके बाद संशोधन अधिनियम कहा जाता है) प्रश्नगत है।
- 2) याचिकाकर्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हांसी में कपास की खरीद और बिक्री का व्यवसाय करती है। 1 नवंबर, 1966 से पहले, हांसी पंजाब राज्य का हिस्सा था (Hereinafter referred to as the Old Punjab). पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा पंजाब के पुनर्गठन के बाद (अधिनियम सं. 1966 का 31) नियत दिन अर्थात् 1 नवंबर, 1966 से पुराने पंजाब के राज्यक्षेत्र को हरियाणा राज्य, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, पंजाब राज्य (नया पंजाब) बनाने के लिए विभाजित किया गया था और राज्यक्षेत्रों का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया गया था।
- 3) पुनर्गठन अधिनियम, धारा 2 में, 'पुराने पंजाब' को मौजूदा पंजाब राज्य के रूप में परिभाषित करता है, जिसका नाम पंजाब राज्य है जो नियत दिन से ठीक पहले मौजूद था। पंजाब के नए राज्य को धारा 2 (1) में उसी नाम के राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 6 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र शामिल हैं। वर्तमान पंजाब राज्य के संबंध में धारा 2 (एम) में उत्तराधिकारी राज्य से पंजाब या हरियाणा राज्य अभिप्रेत है और इसमें चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र और अंतरित राज्यक्षेत्र के संबंध में संघ भी सम्मिलित है। धारा 2 (एन) 'हस्तांतरित क्षेत्र' को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है, जिसे नियत दिन पर मौजूदा पंजाब राज्य से हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- 4) नियत तिथि तक, याचिकाकर्ता मूल अधिनियम द्वारा शासित था (Punjab General Sales Tax Act, 1948, as amended up to date). वे एक पंजीकृत विक्रेता थे और आज भी हैं। पुनर्गठन अधिनियम से पहले, याचिकाकर्ता मूल अधिनियम के तहत अपने कारोबार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि वर्तमान याचिका में, हम केवल केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर घोषित वस्तुओं की बिक्री या खरीद से संबंधित हैं (Act Number 74 of 1956). इन वस्तुओं को मूल अधिनियम की अनुसूची 'सी' में निर्दिष्ट किया गया है। तत्काल मामले में, हम केवल कपास की बिक्री या खरीद से संबंधित हैं जो एक घोषित वस्तु है और इस पर कोई विवाद नहीं है। मूल अधिनियम के तहत घोषित वस्तुओं की खरीद से संबंधित मुख्य प्रावधान धारा 2 थे (ff). 2 (i) 5 (1) और 5(2). भवानी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य (1) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कपास की खरीद पर कर लगाने को इस तरह के कर लगाने के लिए एक ही चरण निर्धारित करने के अभाव में अधिकार से बाहर घोषित कर दिया। इस निर्णय के कारण, खरीद पर सभी शुल्क और कर का संग्रह। 1 अप्रैल, 1960 से कपास अवैध हो गया। संदर्भ की सुविधा के लिए, मैंने उच्च न्यायालय के निर्णय से उस विधान के संक्षिप्त इतिहास को उद्धृत करने की स्वतंत्रता ली है जिसके कारण विवाद हुआ जिसे उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझा लिया गया था: -

"* * * मूल अधिनियम से जुड़ी अनुसूची में, जैसा कि यह 1958 से पहले था, जिसमें कुछ वस्तुओं को बिक्री कर से छूट दी गई थी, जिन वाले या गैर-जिन वाले कपास को मद सं. 29. वर्ष 1958 में पूर्वी पंजाब

सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1958 द्वारा (1958 का पंजाब अधिनियम 7) मद संख्या 29 को अनुसूची से हटा दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कपास (जालीदार या बिना जालीदार) बिक्री कर के लिए उत्तरदायी हो गया था। 'खरीद' शब्द की परिभाषा पहली बार 1958 के पंजाब अधिनियम 7 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 2 में पेश की गई थी। इस परिभाषा के अनुसार-'2 (एफएफ)' 'खरीद', अपने सभी व्याकरणिक या संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ, उपयोग के लिए गन्ना, खाद्यान्न और दालों के अलावा अन्य वस्तुओं का अधिग्रहण, बिक्री या नकद या आस्थगित भुगतान के लिए माल का निर्माण, बंधक, परिकल्पना के अलावा मूल्यवान प्रतिफल; शुल्क या गिरवी:

* * * •

- 5) पंजाब अधिनियम 1959 द्वारा 'चीनी खाद्यान्न और दालों के अलावा' शब्दों को हटा दिया गया था। "1959 के पंजाब अधिनियम 24 द्वारा किए गए संशोधन के बाद, खंड (एफएफ) इस प्रकार था:-(एफएफ)' सभी व्याकरणिक या संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ 'खरीद' का अर्थ है अनुसूची सी में निर्दिष्ट वस्तुओं का अधिग्रहण जिसका उपयोग माल के निर्माण में नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए बिक्री के लिए उपयोग किया जाता है, जो बंधक, परिकल्पना, शुल्क या गिरवी के तहत नहीं है।
- 6) 1958 के पंजाब अधिनियम 7 द्वारा प्रदत्त कर की दर वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर 4 प्रतिशत थी। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम। 1958, दिसंबर में अधिनियमित किया गया था। 1956 में। उस अधिनियम की धारा 14 ने अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में कई वस्तुओं को विशेष महत्व का घोषित किया। इनमें से एक था 'कोट\टन', अर्थात्, सभी प्रकार की कपास (स्वदेशी या आयातित) अपनी निर्मित अवस्था में, चाहे वह जालीदार हो या बिना जालीदार, गांठदार, दबाए हुए या अन्यथा, • नहीं। कपास अपशिष्ट सहित। धारा 15, 4958 के केंद्रीय अधिनियम 31 द्वारा संशोधित के रूप में, प्रदान करता है -

"15. किसी राज्य की प्रत्येक बिक्री कर विधि, जहां तक वह घोषित वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर कर अधिरोपित करने को प्राधिकृत करती है, निम्नलिखित अवरोधनों और शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:-(क) राज्य के भीतर ऐसी वस्तुओं के विक्रय या क्रय के संबंध में उस विधि के अधीन संदेय कर उसके विक्रय या क्रय मूल्य के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ऐसा कर एक से अधिक स्तर पर नहीं अधिरोपित किया जाएगा; (ख) जहां राज्य के भीतर किसी घोषित वस्तु के विक्रय या क्रय के संबंध में उस विधि के अधीन कर अधिरोपित किया गया है और ऐसी वस्तुएं अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में बेची जाती हैं, वहां इस प्रकार अधिरोपित कर ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए वापस किया जाएगा जो उस में प्रवृत्त किसी विधि में उपबंधित की जाएं। राज्य "।
चूंकि 1958 का पंजाब अधिनियम 7 एक ही वस्तु पर चार प्रतिशत की दर से खरीद और बिक्री दोनों कर लगाता था, और राज्य में एक से अधिक स्तरों पर एक रिट याचिका के माध्यम से इसके अधिकारों पर हमला किया गया था, जिसे इस अदालत की एक पीठ द्वारा तय किया गया था, निर्णय को मेसर्स रघबीर चंद-सोम चंद बनाम आबकारी और कराधान अधिकारी के रूप में रिपोर्ट किया जा रहा है।

अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जूट के विक्रेता राज्य के भीतर की गई बिक्री पर केवल दो प्रतिशत से अधिक कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और जब वे अपने माल का निर्यात करते थे और राज्य के बाहर की बिक्री को प्रभावित करते थे तो वे किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। राज्य। इसके बाद राज्य विधानमंडल ने पंजाब सामान्य बिक्री कर (संशोधन और वैधता) अधिनियम लागू किया। 1960 का दशक (Punjab Act 17 of 1960). इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों का उल्लेख करना अनावश्यक है क्योंकि इसे पंजाब सामान्य बिक्री कर (संशोधन और वैधता) निरसन अधिनियम 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 28) द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित किया गया था। एक और अधिनियम, पंजाब जनरल। बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का पंजाब अधिनियम 18) अधिनियमित किया गया था जिसने 'खरीद' शब्द की परिभाषा को बदल दिया। परिवर्तित परिभाषा इस प्रकार है: -(2) "क्रय" "से उसके सभी व्याकरणिक या संज्ञानात्मक शब्दों के साथ अभिप्रेत

है-अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट माल का नकद या विलम्बित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए अधिग्रहण, जो बंधक, परिकल्पना, प्रभार या गिरवी के अधीन नहीं है।"

उसी अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा 5 (1) का दूसरा परन्तुक अंतःस्थापित किया गया था। को। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित किसी घोषित माल की बाबत कर की दर एक रुपये में दो नए पैसे से अधिक नहीं होगी और ऐसा कर एक से अधिक स्तर पर ऐसे माल की खरीद या बिक्री पर नहीं लगाया जाएगा।

मूल अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) का उपखंड, जैसा कि आई960 के पंजाब अधिनियम 18 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, इस प्रकार है-"(vi) उन वस्तुओं की खरीद जो वर्ष के अंत के छह महीने के बाद, किसी पंजीकृत विक्रेता को, या अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पाठ्यक्रम में, या भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान बेची जाती हैं: बशर्ते कि किसी पंजीकृत, विक्रेता को ऐसी बिक्री के मामले में, एक घोषणा, निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरी और हस्ताक्षरित पंजीकृत विक्रेता द्वारा, जिसे माल बेचा जाता है, उसे प्रस्तुत किया जाता है-विक्रेता द्वारा, कटौती का दावा करते हुए, * * *

- 7) उपर्युक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को उनके बाद के संशोधनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिन्हें संदर्भ की सुविधा और हमारे निर्णय की उचित समझ के लिए इस निर्णय के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल, 1967 को भवानी कॉटन मिट्स के मामले का फैसला किया और तब तक पुराने पंजाब राज्य का विघटन हो चुका था। इस निर्णय से उबरने के लिए, हरियाणा और पंजाब की विधानसभाओं ने कर के पुराने शुल्कों को मान्य करने के लिए कदम उठाए, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया था। हरियाणा में इस दिशा में पहला कदम पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और वैधता) अध्यादेश, 1967 नामक एक अध्यादेश द्वारा उठाया गया था। इस अध्यादेश को संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसे हरियाणा राज्य के विधायी निकाय के लिए कार्य करने वाली केंद्रीय संसद द्वारा पारित किया गया था, क्योंकि इस बीच, राष्ट्रपति शासन ने हस्तक्षेप किया था और हरियाणा का विधानमंडल काम नहीं कर रहा था। यह इस संशोधन अधिनियम के अधिकार हैं, जिन पर वर्तमान याचिका में विभिन्न आधारों पर सवाल उठाए गए हैं, जिनकी गणना आगे की जाएगी। हम याचिका में लिए गए आधारों में से केवल उन आधारों का उल्लेख करने का प्रस्ताव करते हैं जो वास्तव में हमारे सामने आंदोलन कर रहे हैं। इस याचिका के प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य द्वारा अपने बदले में लिए गए रुख का विज्ञापन किया जाए क्योंकि हमारे सामने प्रचार किए गए प्रश्न विशुद्ध रूप से कानून के हैं। हरियाणा के जाने-माने महाधिवक्ता श्री आनंद स्वरूप ने भी रिट याचिका की रूपरेखा के संबंध में कुछ तकनीकी याचिकाएं उठाने का अनुरोध किया। लेकिन, हमारी राय में जहां तक हमारे सामने प्रचार किए गए प्रश्नों का संबंध है, उन आपत्तियों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। उत्तेजित किए गए प्रश्न विशुद्ध रूप से कानूनी प्रकृति के हैं। हालांकि, सभी विवादों से बचने के लिए, हमने याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश दिया कि वे कुछ तथ्यों का अनुरोध करते हुए एक बेहतर हलफनामा दायर करें, जो श्री आनंद स्वरूप के अनुसार, उठाए गए कानूनी मुद्दों के निर्धारण के लिए आवश्यक हैं। वह हलफनामा दाखिल किया गया है और इसलिए इसका जवाब दिया गया है।
- 8) विभिन्न मुद्दे, जो अब हमारे सामने उठाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं-(1) कि हरियाणा राज्य के पास उस क्षेत्र के लिए पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है, जो 1 नवंबर, 1966 को बनने से पहले हरियाणा नहीं था। यह नहीं है। इस बात पर विवाद था कि 1 नवंबर, 1966 के बाद, हरियाणा राज्य संभावित और पूर्वव्यापी दोनों तरह से कानून बना सकता है। लेकिन इसके पास 1 नवंबर से पहले की अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। 1966, क्योंकि उस अवधि से पहले, हरियाणा राज्य नहीं था; (2) कि विवादित कानून भेदभावपूर्ण है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद * 14 का उल्लंघन करता है। यह तर्क दिया जाता है कि 1 नवंबर तक। 1966 में। पंजाब एक ऐसा राज्य था जिसमें से 1 नवंबर, 1966 के बाद हरियाणा राज्य, नया पंजाब राज्य, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और हस्तांतरित क्षेत्र, जो हिमाचल प्रदेश में चले गए, उभरे। जहां तक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़

और हस्तांतरित क्षेत्रों का संबंध है, संशोधन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एकमात्र क्षेत्र जहाँ विवादित अधिनियम लागू होता है, वह पुराना पंजाब का क्षेत्र है, जो अब हरियाणा का हिस्सा है। पुराने पंजाब के क्षेत्र के संबंध में, जो अब नया पंजाब है, कुछ इसी तरह का प्रावधान किया गया है; लेकिन यह हरियाणा के कानून के साथ पूरी तरह से नहीं है। इसलिए, यह कहा जाता है कि पुराने पंजाब के क्षेत्र के संबंध में, जिसमें से नए राज्य और क्षेत्र बनाए गए हैं, एक ही विषय पर समान व्यक्तियों के लिए समान रूप से स्थित कोई समान कानून नहीं है।

संशोधन अधिनियम का पूर्वव्यापी प्रवर्तन उस समय से शुरू होता है जब पुराना पंजाब था, और इसलिए, हरियाणा और पंजाब में अब इसके क्षेत्र के लिए समानांतर अधिनियम बनाए गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ या स्थानांतरित क्षेत्रों के लिए ऐसा कोई अधिनियम नहीं होने से अनुच्छेद 14 (3) का स्पष्ट उल्लंघन होगा कि संशोधन अधिनियम के बावजूद, अवैधता, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले आकलनों को रद्द कर दिया था, अभी भी बनी हुई है और संशोधन अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही उसी बुराई से पीड़ित होने का दावा करती है जब मामला भवानी कॉटन मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय में गया था।

इस पर और जोर दिया जाता है: -

(1) जो पहले अमान्य था उसे वैध बनाने के लिए संशोधन अधिनियम द्वारा दिए गए पूर्वव्यापी संचालन के बावजूद, अधिनियम के तहत नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। ऐसा कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सके कि घोषित वस्तुओं पर कर लगाया गया है या नहीं। पहले चरण में; और (ii) अधिनियम ने निर्धारणों को फिर से खोलने को वैकल्पिक बना दिया है; और इसलिए, अधिनियम केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15 के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, जिन आकलनों को फिर से खोला जा सकता है, वे केवल हरियाणा के हैं। यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि क्या बिक्री कर के रूप में निर्धारित की जाने वाली वस्तुओं को पहले से ही पुराने पंजाब के क्षेत्र को छोड़कर पुराने पंजाब में इसके अधीन किया गया था, जो अब हरियाणा राज्य है और केंद्रीय अधिनियम (केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956) भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रिलायंस को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, मद्रास और अन्य बनाम संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य मामलों में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ईस्ट इंडिया सैंडल ऑयल डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया है।

तर्क सं (1)

9) जहाँ तक इस विवाद का संबंध है, यह सामान्य आधार है कि हरियाणा के राज्य विधानमंडल के पास संभावित और साथ ही पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह कहा गया है कि विधानमंडल के पास उन कानूनों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है जो अस्तित्व में आने की तारीख से पहले पूर्वव्यापी प्रभाव रखते हैं। दूसरे शब्दों में, हरियाणा राज्य 1 नवंबर, 1966 को अस्तित्व में आया। इस तारीख से पहले ऐसा कोई राज्य नहीं था। हरियाणा का क्षेत्र पुराने पंजाब का क्षेत्र था। पुराने पंजाब में एक विधानमंडल था जो कानून बना सकता था और इसने उस क्षेत्र के लिए कानून बनाए। अतः हरियाणा के राज्य विधान-मंडल द्वारा 'अधिनियमित' कोई विधि, जो 1 नवम्बर, 1966 से पूर्ववर्ती प्रभाव लेती है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होगी और इस प्रकार संशोधन अधिनियम, जहाँ तक वह 1 नवम्बर, 1966 से पूर्व की अवधि के लिए विक्रय कर की वसूली के लिए विधि बनाता है,

उसकी शक्तियों से परे है और उसे निरस्त किया जाना चाहिए: इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने अनुच्छेद 245 और 246 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 1,2,3 और 4 पर भरोसा रखा। उन्होंने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों और 'विशेष रूप से' धारा 2,6,7,50,55,63,64,65, 88,89 और 90 पर भी भरोसा जताया। इसके अलावा, विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया: -

- (1) एच. एच. भैरव राव मालोजी राव भोरपड़े बनाम कृषि आय-कर अधिकारी और अन्य।
- (2) एन. एन. अनंतनारायण अय्यर और अन्य बनाम कृषि आयकर और बिक्री कर अधिकारी और अन्य।
- (3) भारत संघ बनाम मदन गोपाल काबरा।
- (4) बॉम्बे राज्य बनाम आर. एम. डी. चनारबागवाला और अन्य।
- (5) टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य।
- और (6) खांडिगे शाम भट और के. कृष्ण भट्ट बनाम कृषि आय-कर अधिकारी, कासरगोड और अन्य।

सभी सुसंगत उपबंधों और हमारे समक्ष उद्धृत विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात् हमारा यह मत है कि हाजी अब्दुल शुक्र एंड कं में उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह विवाद विफल होना चाहिए। मद्रास राज्य रिपोर्ट के पृष्ठ 1735 पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ इस मामले को पुष्ट करती हैं:- "राज्य विधायिका ऐसे कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है जिनका पूर्वव्यापी संचालन होगा। अतीत की एक निश्चित अवधि के लिए कानून बनाने की इसकी क्षमता, इसकी वर्तमान विधायी शक्ति पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि इसके अधिनियमन के लागू होने की अवधि में उसके पास क्या था।"

- 10) समान प्रभाव के लिए वरदाचारियार की टिप्पणियाँ, संयुक्त प्रांत बनाम माउंट। अतीका बेगम और अन्य, रिपोर्ट के पृष्ठ 43 पर, विद्वत न्यायाधीश ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:- अब आक्षेपित अधिनियम की अयोग्यता के प्रश्न पर कार्यवाही करते हुए, पहले उस आधार को लेना सुविधाजनक होगा जिस पर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के सभी विद्वत न्यायाधीश सहमत थे, अर्थात्, संविधान अधिनियम की धारा 292 पर आधारित आपत्ति। जैसा कि मैं तर्क को समझता हूँ, यह आपत्ति धारा 292 की व्याख्या केवल इस अधिनियम के रूप में नहीं करती है कि भाग III, संविधान अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले ब्रिटिश भारत में लागू कानून, भारत सरकार अधिनियम के पूर्ववर्ती निरसन के बावजूद लागू रहेगा, बल्कि एक समय-सीमा भी निर्धारित करता है जिसके लिए ऐसी कानून के संचालन को किसी भी अधिनियम में निहित किसी भी चीज़ से बाधित नहीं किया जाना चाहिए जो ब्रिटिश भारत में किसी भी विधानमंडल द्वारा पारित किया जा सकता है। हमारे समक्ष यह स्वीकार किया गया था और उच्च न्यायालय के समक्ष यह मान्यता दी गई थी कि धारा 292 जैसे प्रावधान को आम तौर पर समान अधिनियमों में डाला जाता है, यह इंगित करने के लिए कि मूल अधिनियम के निरसन को उस अधिनियम के तहत पारित सभी कानूनों को निरस्त नहीं माना जाएगा (Compare Section 108, Commonwealth of Australia Constitution Act, Section 129, British North America Act and Section 135, Union of South Africa Act). लेकिन 'परिवर्तित या निरसित या संशोधित होने तक' शब्दों पर विशेष बल देते हुए वादी के लिए विद्वत वकील ने धारा 292 को संसद द्वारा एक निर्देश के रूप में पढ़ने की इच्छा व्यक्त की कि उस समय लागू कानून को किसी भी स्थिति में एक निर्दिष्ट तिथि, अर्थात् भारत में विधानमंडलों के बाद के अधिनियम द्वारा इसके परिवर्तन, निरसन या संशोधन की तारीख तक जारी रहना चाहिए; और इससे यह निष्कर्ष निकालने की मांग की गई थी कि ऐसे विधानमंडलों का कोई भी बाद का अधिनियम पूर्वव्यापी संचालन के शब्दों द्वारा अपने प्रभाव का पूर्व-निर्धारण नहीं कर सकता है ताकि पिछले कानून के तहत प्राप्त अधिकारों को नए विधान की तारीख तक प्रभावित किया जा सके। एक स्तर पर, वादी के विद्वान वकील ने यह भी सुझाव दिया कि भारत में विधानमंडलों को पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी समय कानून बनाने की शक्ति के इस प्रावधान से

वंचित कर दिया गया था, या वे कम से कम 1 अप्रैल, 1937 से पहले की अवधि तक अपने अधिनियमों के पूर्वव्यापी संचालन का विस्तार करने में असमर्थ थे, जब संविधान अधिनियम प्रांतों में लागू हुआ था। हालांकि, इन तर्कों पर जोर नहीं दिया गया था, जब यह बताया गया था कि भारतीय विधानमंडल, उन्हें सौंपी गई वैधानिक सीमाओं के भीतर, पूर्ण शक्तियों वाले निकाय थे: देखें रेग बनाम बुराह आर्चीबाल्ड जी. हॉज बनाम रेग। और क्रॉफ्ट बनाम डंफी, और यह कि पूर्वव्यापी विधान की तर्कसंगतता या समीचीनता के आधार पर जो भी आपत्ति हो सकती है, धारा 292 में भारतीय विधानमंडलों को पूर्ण विधायी शक्ति की इस विशेष घटना से वंचित करने के लिए कुछ भी नहीं था।

आपत्ति तब किसी अधिनियम को पूर्वव्यापी संचालन देने की विधानमंडल की शक्ति तक सीमित थी, जब ऐसा करने से, यह संविधान अधिनियम के भाग III के प्रारंभ की तारीख को अस्तित्व में किसी कानून को निरस्तीकरण या संशोधन अधिनियम की तारीख तक अपने पूर्ण प्रभाव से रोक देगा। यह इंगित किया गया था कि संविधान अधिनियम की धारा 292 में प्रयुक्त भाषा, ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम या ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल अधिनियम के संबंधित प्रावधानों में पाई जाने वाली भाषा के समान नहीं थी। लेकिन, यह प्रतीत होता है कि यह भाषा दक्षिण अफ्रीका संघ अधिनियम की धारा 135 में पाई जाने वाली भाषा से इतनी मिलती-जुलती है कि यह सुझाव देता है कि यह इससे ली गई होगी। अलग-अलग कारणों से दी गई दो प्रकार की छूट का सह-अस्तित्व अकल्पनीय या असंभव नहीं है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विवादित अधिनियम ने भूस्वामियों को किराए के उस हिस्से से वंचित कर दिया, जिस पर उन्होंने पहले ही अधिकार हासिल कर लिया था। लेकिन यदि विधानमंडल के सामान्य सिद्धांतों पर सामान्य रूप से शक्ति है-उन कारणों के लिए जो न्यायालय के लिए ऐसे उपायों को अधिनियमित करने के लिए जांच करने के लिए खुला नहीं है जो किसी विशेष आधार पर मामले को प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से, यह कहने का कोई कारण नहीं है (जैसा कि न्यायमूर्ति बाईबाई ने कहा है) कि 'आक्षेपित अधिनियम ने अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है जो वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता था।'

- 11) भारत संघ बनाम मदन गोपाल काबरा में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया जा सकता है पृष्ठ 162 पर, निम्नलिखित टिप्पणियां होती हैं: -
- "फिर भी, यह तर्क दिया गया था कि वित्त अधिनियम, 1950, जहां तक यह प्राधिकरणों के लिए इस तरह के लेवी का तात्पर्य है, 'अधिकार से बाहर' है और अमान्य है क्योंकि संसद संविधान के तहत इस तरह का कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं थी। तर्क को दो तरीकों से रखा गया था। सबसे पहले, मोटे तौर पर यह कहा गया था कि चूंकि संविधान पूर्वव्यापी रूप से कार्य नहीं कर सकता था जैसा कि इस न्यायालय ने केशवन बनाम बॉम्बे राज्यों में अभिनिर्धारित किया था, इसलिए संसद को संविधान द्वारा प्रदत्त विधान की शक्ति का विस्तार इस प्रकार नहीं किया जा सकता था कि संविधान के प्रारंभ से पहले होने वाली आय को पूर्वव्यापी रूप से प्रभारित किया जा सके। यह एक भ्रांति है।
- हालांकि यह सच है कि संविधान का कोई पूर्वव्यापी संचालन नहीं है, सिवाय इसके कि जहां एक अलग इरादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यह कहना सही नहीं है कि नए विधानमंडलों को अस्तित्व में लाने और उन्हें कानून बनाने की कुछ शक्तियां प्रदान करने में, संविधान पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है। संसद को अनुच्छेद के तहत विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं। 245 और कला। सातवीं अनुसूची की सूची। के साथ पठित 246 का प्रयोग स्पष्ट रूप से संविधान के लागू होने के बाद ही किया जा सकता था और उन शक्तियों को प्रदान करने में संविधान का कोई पूर्वव्यापी संचालन शामिल नहीं है। लेकिन यह कहना एक अलग बात है कि इस प्रकार अर्जित शक्तियों का प्रयोग करने में संसद पूर्वव्यापी कानून बनाने से वंचित है। प्रश्न प्रदत्त शक्तियों के दायरे पर निर्भर होना चाहिए, और इसका निर्धारण उस साधन की शर्तों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसके द्वारा सकारात्मक रूप से, विधायी शक्तियों का निर्माण किया गया था और जिसके द्वारा, नकारात्मक रूप से, उन्हें प्रतिबंधित किया गया था। (रानी बनाम बुराह) "।

12) अधिकारियों को गुणा करना आवश्यक नहीं है। विद्वान महाधिवक्ता श्री आनंद स्वरूप ने उदाहरणों के माध्यम से हमारा ध्यान ऐसे कई मामलों की ओर आकर्षित किया, जहां राज्य विधानमंडल के अस्तित्व से पहले कानून के पूर्वव्यापी संचालन को इस आधार पर निरस्त नहीं किया गया था कि ऐसे विधानमंडल को उस अवधि के लिए पूर्वव्यापी कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं थी जब वह कभी अस्तित्व में नहीं था। जहाँ तक याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा किए गए निर्णयों का संबंध है, वे स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, एच. एच. भैरव राव मालोजी राव घोरपड़े बनाम कृषि आयकर अधिकारी और एक अन्य मामले में मैसूर उच्च न्यायालय का निर्णय एन. एन. अनंतनारायण अय्यर और अन्य बनाम कृषि आयकर और बिक्री कर अधिकारी और अन्य मामलों में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है (21). वास्तव में, मैसूर का निर्णय केरल के निर्णय का अनुसरण करता है। पी. गोविंदन नायर जे. ने चाको चाको कैथाकुट्टु वीडू और अन्य बनाम राजस्व बोर्ड, केरल राज्य और अन्य (22) में केरल के निर्णय की व्याख्या की है और यही कारण मैसूर के निर्णय को भी शामिल करेगा। पहले से ही विद्वान न्यायाधीश को संदर्भित अपने स्वयं के न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:- "इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ अंश हैं।

उस निर्णय में जो यह इंगित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल में किसी राज्यक्षेत्र के संबंध में किसी अवधि के लिए विधि अधिनियमित करने की कोई शक्ति नहीं है, जो उस अवधि के दौरान राज्य का भाग नहीं था। लेकिन उस मामले में और साथ ही विश्वांबर सिंह बनाम कृषि आय-कर कलेक्टर और मदनगोपाल केबरा बनाम भारत संघ में रिपोर्ट किए गए मामले में वास्तविक निर्णय ने कानून की उस धारा के शब्दों को चालू कर दिया जो कृषि आय-कर के अधिरोपण से संबंधित थी। संबंधित धाराओं में यह प्रावधान है कि कृषि आय निम्नलिखित होनी चाहिए: राज्य के भीतर स्थित भूमि से प्राप्त आय। इसका मतलब यह था कि आय के संचय के समय भूमि राज्य के भीतर होनी चाहिए थी। उपर्युक्त मामलों में निर्णय विशुद्ध रूप से धारा की व्याख्या पर आधारित होने चाहिए और निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित करने के लिए प्राधिकरण नहीं हो सकते हैं कि राज्य विधानमंडल के पास पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। "

हम उपरोक्त टिप्पणियों के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं।

13) यह भारत संघ बनाम मदन गोपाल काबरा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को छोड़ देता है। बॉम्बे राज्य बनाम आर. एम. डी. चमारबागवाला और एक अन्य। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, और खांडीगे शाम भट और के. कृष्ण भट्ट बनाम कृषि आय-कर अधिकारी, कासरगोड और अन्य। मैं पहले ही मदन गोपाल काबरा के मामले को देख चुका हूँ। यह निर्णय किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन नहीं करता है। यह वास्तव में उनके पहले विवाद को नकारता है। अन्य निर्णय विद्वान वकील को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं, और विवाद में मामले पर कोई वास्तविक असर नहीं डालते हैं।

14) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का पहला तर्क विफल होना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

तर्क संख्या 2

15) जहाँ तक दूसरे विवाद का संबंध है, यह वास्तव में इस स्थापित नियम के विपरीत है कि एक राज्य अस्तित्व में आने से पहले ही अपने क्षेत्रों के बारे में पूर्वव्यापी रूप से कानून बना सकता है। विद्वान वकील का तर्क है कि 1 नवंबर, 1966 से पहले हरियाणा राज्य नहीं था। जो अब हरियाणा राज्य है, वह पंजाब

राज्य का हिस्सा था। पंजाब के पुराने राज्य को चार टुकड़ों में विभाजित किया गया है, अर्थात् हरियाणा; केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़; हस्तांतरित क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश और नए राज्य पंजाब में चले गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और हस्तांतरित क्षेत्रों में, उस लेवी को मान्य करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है जिसे भवानी कॉटन मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसलिए, हरियाणा कानून भेदभाव से ग्रस्त है, क्योंकि 1 नवंबर, 1966 से पहले की अवधि से, यह अपने क्षेत्रों के लिए एक प्रावधान लागू करता है, जिसके समान पुराने पंजाब के क्षेत्रों में कोई प्रावधान नहीं है जो हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के दायरे में चले गए हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यदि इस तर्क को प्रभाव दिया जाता है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाजी अब्दुल शंकगोर मामले में निर्धारित नियम को पूरी तरह से नकारात्मक कर देगा। जहाँ तक हरियाणा क्षेत्र का संबंध है, यह विवादित नहीं है कि कानून समान है। वास्तव में, यह तर्क तभी सफल हो सकता है जब विद्वान वकील के पहले तर्क में सार हो। यदि कोई राज्य विधानमंडल संभावित रूप से एक वैध कानून बना सकता है, तो निश्चित रूप से यह पूर्वव्यापी रूप से एक वैध कानून बना सकता है। इसलिए, इस तर्क की जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि नए पंजाब में कानून भी हरियाणा के कानून से अलग है।

- 16) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 और 89 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। (Act No. 31 of 1966). इन प्रावधानों को संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे उद्धृत किया गया है: —

“88. विधियों का प्रादेशिक विस्तार:-भाग 2 के उपबंधों से यह नहीं समझा जाएगा कि वे उन राज्यक्षेत्रों में कोई परिवर्तन प्रभावी करते हैं जिन पर नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त कोई विधि विस्तारित होती है या लागू होती है, और पंजाब राज्य के लिए ऐसी किसी विधि में प्रादेशिक निर्देश, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया जाता है, का अर्थ नियत दिन से ठीक पहले उस राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्रों के रूप में किया जाएगा।

89. कानूनों को अपनाने की शक्ति:-पंजाब या हरियाणा राज्य या हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में नियत दिन से पहले बनाई गई किसी विधि के आवेदन को सुगम बनाने के प्रयोजनों के लिए, उपयुक्त सरकार, उस दिन से दो वर्ष की समाप्ति से पहले, आदेश द्वारा, विधि के ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकती है, चाहे निरसन या संशोधन के रूप में, जो आवश्यक या समीचीन हो, और फिर ऐसी प्रत्येक विधि का प्रभाव किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार किए गए परिवर्तन, निरसन या संशोधन के अधीन होगा।

स्पष्टीकरण:-इस धारा में 'समुचित सरकार' पद का अर्थ है-(क) संघ सूची, केन्द्रीय सरकार में प्रगणित किसी मामले से संबंधित किसी विधि के संबंध में; और (ख) किसी अन्य विधि के संबंध में-(i) किसी राज्य, राज्य सरकार को उसके आवेदन में, और (ii) किसी संघ राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार को उसके आवेदन में।”

- 17) इन प्रावधानों के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि पुनर्गठन अधिनियम नए राज्यों के विधानमंडलों को उनके जन्म से पहले की अवधि को कवर करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून पारित करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विशेष रूप से राज्य विधानमंडल में निहित शक्ति को अपने क्षेत्रों के लिए पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने से रोकता है। लेकिन धारा 88 और 89 के प्रावधानों से यह इंगित करने का प्रयास किया गया है कि राज्य विधानमंडल में अपने क्षेत्रों के लिए पूर्वव्यापी विधियों को अधिनियमित करने की अंतर्निहित शक्ति को नकार दिया गया था और केवल नए राज्यों को उनके जन्म से ही संभावित रूप से विधियों को अधिनियमित करने की शक्ति दी गई थी। हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते। धारा 88 विधियों के क्षेत्रीय विस्तार से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, यह पुराने पंजाब कानून को नए राज्यों या क्षेत्रों का कानून बनाता है जब तक कि इसे सक्षम विधानमंडलों द्वारा अन्यथा परिवर्तित नहीं किया जाता है। धारा 89 केवल अनुकूलन की शक्ति प्रदान करती है और किसी भी राज्य या उसके क्षेत्रों द्वारा पूर्वव्यापी रूप से

कानूनों को पारित करने से मना नहीं करती है। इसलिए, दूसरे तर्क का भी कोई औचित्य नहीं है और इसे विफल होना चाहिए।

तर्क संख्या 3

- 18) इस शीर्ष के तहत विभिन्न तर्क दिए गए हैं और उनकी एक-एक करके जांच की जाएगी: -
पहली शर्त यह है कि संशोधन अधिनियम धारा 14 और केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप नहीं है क्योंकि कर के एकल बिंदु उद्ग्रहण के लिए कोई निश्चित चरण का संकेत नहीं दिया गया है। यह कहा गया है कि हरियाणा में, अंतिम खरीद या बिक्री पर एक बार कर लगाया जाएगा और इसी तरह पंजाब में भी; और इसलिए, प्रत्येक राज्य को, 1 नवंबर, 1969 से पहले, अपने क्षेत्रों के लिए ऐसा कर लगाने का अधिकार होगा। प्रभाव यह हो सकता है कि पुराने पंजाब क्षेत्र में, कपास पर कर लगाया जा सकता है जो एक घोषित वस्तु है। पंजाब या हरियाणा अधिनियमों में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है कि यदि उसी वस्तु पर विभाजन से पहले पंजाब में कर लगाया गया था, तो विभाजन के बाद हरियाणा में और इसके विपरीत उस पर कर नहीं लगाया जाएगा। यह कहा जाता है कि इस पाठ्यक्रम से उसी वस्तु पर उस अवधि के लिए दोहरा कराधान होगा जब पंजाब राज्य एक था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्रीय अधिनियम के तहत, घोषित माल पर या तो बिक्री के स्थान पर या खरीद के स्थान पर राज्य के भीतर केवल एक ही लेवी की अनुमति है; और यदि परिणाम, जिसकी परिकल्पना की गई है, उसका पालन करता है, तो दूसरा लेवी अमान्य होगा। यह केवल तभी माना जाएगा जब एक ही वस्तु पर वास्तव में दो बार कर लगाया जाए। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि एक ही वस्तु पर दो बार कर लगाया गया है। केवल यह तथ्य कि एक ही वस्तु पर कर लगाया जा सकता है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अधिनियम खराब है। अधिनियम अपने क्षेत्रों के लिए यह नहीं कहता है कि एक ही वस्तु पर दो बार कर लगाया जाए। इसका उद्देश्य केवल एक बार कर लगाना है। लेकिन अगर पंजाब के पुनर्गठन के कारण ऐसा परिणाम सामने आ सकता है, तो यह इसलिए नहीं है कि अधिनियम खराब है, बल्कि इसलिए है क्योंकि एक निश्चित घटना ने हस्तक्षेप किया है, अर्थात्, पंजाब का विभाजन: और यदि एक ही वस्तु पर, 1 नवंबर, 1966 से पहले, दो बार कर लगाया जाता है और यह तथ्य साबित हो जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता राहत का हकदार होगा।
लेकिन वह आकस्मिकता तभी उत्पन्न होगी जब एक मूल्यांकन किया गया हो। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, ऐसा कोई आरोप नहीं है।
- 19) इसके बाद यह माना जाता है कि यदि दोहरे कराधान की संभावना है, तो कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। यह तर्क इस तथ्य की दृष्टि खो देता है कि हरियाणा अधिनियम के तहत दोहरे कराधान की कोई संभावना नहीं है। यह संभावना तभी संभव हो सकती है जब पंजाब और हरियाणा अधिनियमों के संचालन पर साथ-साथ विचार किया जाए; और वह भी ऐसे मामलों के एक वर्ग में, जहां पंजाब और हरियाणा दोनों एक ही वस्तु पर दो बार कर लगा रहे हैं, जहां या तो बिक्री या खरीद 1 नवंबर, 1956 से पहले हुई थी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इससे पंजाब या हरियाणा का कानून खराब नहीं हो सकता। यह केवल दूसरे लेवी को खराब कर देगा; और जब भी ऐसा कोई मामला आता है, तो दूसरे लेवी को हमेशा रद्द किया जा सकता है।
- 20) अगला तर्क यह है कि संशोधन अधिनियम भवानी कोट-टैन मिल्स मामले में परिकल्पित कर के उद्ग्रहण के चरण को निर्धारित नहीं करता है। वास्तव में, संशोधन अधिनियम ने लेन-देन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, अर्थात्:-(क) 1 अक्टूबर, 1958 से 31 मार्च, 1960 तक; (ख) 1 अप्रैल, 1960 से 13 नवंबर, 1967 तक; और (ग) 14 नवंबर, 1967 से और उसके बाद।
जहां तक पहली अवधि का संबंध है, कर की दर एक रुपये में दो पैसे है और यह देय और देय है-(ख) जहां ऐसे माल को बिक्री के लिए माल के निर्माण में उपयोग के लिए खरीदा गया था, खरीद पर, उस स्तर पर जब वे इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी विक्रेता द्वारा खरीदे गए थे; और

- (ग) जहां इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अंतिम विक्रेता द्वारा बिक्री के स्तर पर बिक्री के लिए माल के निर्माण में उपयोग के लिए ऐसी वस्तुओं की खरीद नहीं की गई थी।
- 21) दूसरी अवधि के लिए; केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (ii) और (vi) में निर्दिष्ट घोषित वस्तुओं के संबंध में फैक्स इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अंतिम डीलर द्वारा खरीद के चरण में देय और देय है। तीसरी अवधि के लिए, सभी घोषित वस्तुओं के संबंध में, कर एक रुपये में तीन पैसे है और अनुसूची डी में ऐसी वस्तुओं के खिलाफ विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, जैसा भी मामला हो, बिक्री या खरीद के चरण में देय और देय है। बशर्ते कि अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट माल के मामले में कर केवल उसकी खरीद पर ही देय और देय होगा।
- 22) अधिनियम की अनुसूची डी
- 23) याचिका के लिए विद्वत वकील द्वारा यह विवादित नहीं है कि संशोधन अधिनियम, जहां तक वह 1 अक्टूबर, 1958, मार्च, 1960 की धारा 0.31 से संबंधित है, किसी दोष से ग्रस्त नहीं है। जहाँ तक दूसरे चरण का संबंध है, यह अधिनियम मैसूर, आंध्र प्रदेश, संयुक्त प्रांत और मद्रास अधिनियम के समान है। इन अधिनियमों को भवानी कॉटन मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा इस तर्क पर विचार करते हुए देखा गया था कि इन अधिनियमों में निर्धारित चरण के विपरीत विवादित पंजाब अधिनियम में कोई भी चरण तय नहीं किया गया था। उस दोष को संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है और इसने मूल अधिनियम को उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपतियों द्वारा देखे गए अधिनियमों के अनुरूप बना दिया है। एक व्यावसायिक लेन-देन में, एक चरण तय करने के बावजूद, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां चरण को दूसरी बार दोहराया जा सकता है; उदाहरण के लिए, एक गैर-पंजीकृत विक्रेता के हस्तक्षेप से। ऐसे मामलों में, दूसरा शुल्क हमेशा रद्द किया जा सकता है। केवल इस तथ्य से कि दूसरा अवैध लेवी निरस्त कर दिया गया है या उचित नहीं है, एक निष्कर्ष आवश्यक रूप से यह नहीं बताता है कि अधिनियम खराब है। केंद्रीय कानून के लिए केवल इतना आवश्यक है कि कर लगाने के लिए एक चरण निर्धारित किया जाना चाहिए, इसका कारण यह है कि कर एक बिंदु पर लगाया जाना चाहिए। राज्य का कानून इस बात को तय करता है। लेकिन मानव मामलों में, एक ऐसा कानून बनाना असंभव है जो सभी संभावित और कल्पना करने योग्य संभावनाओं की कल्पना करेगा और एक कानून पर हमला करना बहुत अधिक होगा क्योंकि इसमें ऐसी सभी कल्पना करने योग्य संभावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसके अलावा, मद्रास और अन्य संबद्ध अधिनियमों की वैधता पर उनके प्रभुओं द्वारा कोई संदेह नहीं किया गया था, जिसके लिए एक संदर्भ दिया गया था, और चूंकि विवादित राज्य अधिनियम उन अधिनियमों के अनुरूप है, इसलिए हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि अधिनियम खराब है क्योंकि यह घोषित वस्तुओं के संबंध में कराधान का एक विशिष्ट बिंदु तय करने में विफल रहा है। यदि कोई मामला सामने आता है, जहां दोहरी वसूली की गई है, तो न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा। हमें इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि यदि दोहरे शुल्क को बिक्री कर अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है, तो वे इसे भी बंद कर देंगे। इसके अलावा, कर केवल पंजीकृत विक्रेता पर लगाया जाता है; और यदि कोई व्यापारी, जो माल का सौदा करता है और कानून के तहत, खुद को पंजीकृत करता है: ऐसा नहीं करता है और कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करके माल को दोहरे कराधान के लिए उत्तरदायी बनाता है, तो यह कानून को अमान्य नहीं करेगा। यह मौलिक है कि कानून के उल्लंघन को अमान्य घोषित करने के लिए नोटिस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए वे यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि दूसरी अवधि, 1 अप्रैल, 1960 से 13 नवंबर, 1967 के लिए कोई चरण निर्धारित नहीं है। इसके अलावा, एक कानून की संवैधानिकता का अनुमान है और बोझ, कि एक निश्चित कानून असंवैधानिक है, उस व्यक्ति पर है जो चाहता है कि इसे अमान्य घोषित किया जाए (श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और अन्य में निर्णय देखें। वर्तमान मामले में बोझ नहीं उठाया गया है।
- 24) जहां तक तीसरी अवधि का संबंध है; तब याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की अनुसूची 'डी' में आयातित और स्थानीय रूप से उत्पादित कपास के बीच भेदभाव किया गया था, जैसे कि कपास हरियाणा राज्य के बाहर से किसी व्यापारी द्वारा आयात किया गया था या अन्यथा उसे

हरियाणा राज्य में बिक्री के लिए प्राप्त किया गया था, अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी एक व्यापारी द्वारा हरियाणा राज्य के भीतर पहली बिक्री पर कर लगाने का चरण तय किया गया है। यदि, दूसरी ओर, कपास हरियाणा राज्य में खरीदा गया था, तो हरियाणा राज्य के भीतर पहली खरीद पर अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी डीलर द्वारा कर लगाया जाना था। विद्वान वकील के अनुसार, बिक्री मूल्य स्पष्ट रूप से खरीद मूल्य से अधिक था और इसलिए, आयातित कपास पर कर की मात्रा स्वाभाविक रूप से स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं की तुलना में अधिक होगी। इस तरह, आयातित वस्तुओं के साथ भेदभाव किया गया और इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) द्वारा प्रभावित किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि यह तथ्य कि कर लगाने के लिए दो चरण निर्धारित किए गए थे, एक बिक्री मूल्य पर और दूसरा आयातित और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं पर खरीद मूल्य पर, यह दर्शाता है कि पूर्व वस्तुओं के साथ भेदभाव किया गया था।

- 25) यह सच है कि अनुसूची 'डी' में, माल और कपास उनमें से एक होने के कारण, यह उल्लेख किया गया है कि यदि कपास का आयात हरियाणा राज्य के बाहर से किसी व्यापारी द्वारा किया गया था या अन्यथा उसे हरियाणा राज्य में बिक्री के लिए प्राप्त किया गया था, तो हरियाणा राज्य के भीतर पहली बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी डीलर द्वारा कर लगाया जाना था और यदि कपास हरियाणा राज्य में खरीदा गया था, तो अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी डीलर द्वारा हरियाणा राज्य के भीतर पहली खरीद पर कर लगाया गया था। हालांकि, सवाल यह उठता है कि इस कानून को बनाने से क्या आयातित और स्थानीय वस्तुओं के बीच कोई भेदभाव किया गया है और क्या यह कानून संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) द्वारा बनाया गया था? अनुच्छेद 304 (ए) का प्रासंगिक भाग कहता है- "304। अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा-(क) अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से आयातित वस्तुओं पर ऐसा कोई कर अधिरोपित कर सकता है जिसके अधीन उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित समान वस्तुएं हैं, तथापि, इस प्रकार कि इस प्रकार आयातित वस्तुओं और इस प्रकार विनिर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच भेदभाव न किया जाए,
- 26) इसका मतलब यह है कि आयातित और स्थानीय वस्तुओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। संविधान के भाग XIU में अनुच्छेद 304 (ए) का उल्लेख है जो भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग से संबंधित है। अनुच्छेद 301 में यह प्रावधान है कि भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग स्वतंत्र होगा, लेकिन यह भाग XIII के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा। ॥ अनुच्छेद 304 के आधार पर है कि राज्य विधानमंडल अन्य राज्यों से आयातित वस्तुओं पर ऐसा कर लगाने के लिए अधिकृत है जिसके लिए उस राज्य में समान वस्तुएं अधीन थीं और राज्य विधानमंडल की इस शक्ति पर लगाई गई एकमात्र सीमा यह है कि कर लगाने से उसे आयातित और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह निर्विवाद है कि हरियाणा राज्य में उत्पादित कपास पर कर लगाया गया है। ऐसा होने के कारण, राज्य विधायिका आयातित कपास पर भी कर लगाने के अपने अधिकारों के भीतर थी। अब विचार करने की बात यह है कि क्या आयातित वस्तुओं पर कर लगाने से उनके और स्थानीय वस्तुओं के बीच कोई भेदभाव हुआ है। यह आम बात है कि खरीद कर और बिक्री कर की दर समान है, यानी 3 प्रतिशत। जब दर समान होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 304 में यह अपेक्षा नहीं की गई है कि आयातित और स्थानीय वस्तुओं पर समान या समान कर लगाया जाए। दूसरे शब्दों में, यदि स्थानीय वस्तुओं पर खरीद कर लगाया गया था, तो यह आवश्यक नहीं है कि केवल आयातित कपास पर खरीद कर लगाया जा सके। अनुसूची 'डी' के अनुसार, आयातित कपास पर कर हरियाणा राज्य में उन वस्तुओं की पहली बिक्री पर लगाया जाता है और स्थानीय कपास पर कर हरियाणा राज्य में पहली खरीद पर लगाया जाता है। जैसा कि हमने कहा है, अनुच्छेद 304 (3) के तहत जो आवश्यक है वह यह है कि आयातित और स्थानीय कपास के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आयातित कपास हरियाणा राज्य में पहुंचता है, तो इसे ऐसा माना जाना चाहिए जैसे कि इसका उत्पादन हरियाणा राज्य में हुआ हो। तभी यह कहा जाएगा कि उनके साथ समान व्यवहार किया जा रहा था। बाहरी कपास के आयातक को

स्थानीय कपास के उत्पादक के बराबर माना जाना चाहिए। जब आयातित कपास हरियाणा राज्य में बेचा जाता है, तो उसके बिक्री मूल्य पर कर लगाया जाएगा। इसी तरह जब हरियाणा राज्य में पहली बार स्थानीय सामान खरीदा जाता है, तो खरीद मूल्य पर कर लगाया जाएगा जो स्पष्ट रूप से पहला बिक्री मूल्य है। ऐसा होने पर, दोनों प्रकार की वस्तुओं में, हरियाणा राज्य में वस्तुओं के पहले बिक्री मूल्य पर कर लगाया जाना है। इस प्रकार दो प्रकार के कपास के बीच कोई भेदभाव नहीं है और उन पर लगाए गए कर की मात्रा में कोई अंतर नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि आयातित और स्थानीय वस्तुओं पर दो अलग-अलग चरणों में कर लगाया जाता है, एक पहली बिक्री मूल्य पर और दूसरा पहली खरीद मूल्य पर, जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव होता है। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, तत्काल मामले में कोई दो चरण नहीं हैं। दोनों ही मामलों में, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, दो प्रकार के कपास के पहले बिक्री मूल्य पर कर लगाया जाना है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि आयातित वस्तुओं का बिक्री मूल्य स्पष्ट रूप से उनके खरीद मूल्य से अधिक होगा, और परिणामस्वरूप कर की मात्रा खरीद मूल्य की तुलना में बिक्री मूल्य पर अधिक होगी। इस तर्क में एक स्पष्ट भ्रंति है। जब विद्वान वकील कहता है कि बिक्री मूल्य स्पष्ट रूप से खरीद मूल्य से अधिक होगा, तो तुरंत एक सवाल उठता है कि किसके खरीद मूल्य से अधिक होगा? यदि सुझाव यह था कि यह आयातक के स्वयं के खरीद मूल्य से अधिक होगा, तो जाहिर है कि आयातित कपास और स्थानीय कपास के बीच किसी भी भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि तुलना केवल इन दो प्रकार के कपास और एक ही तारीख के बीच होनी चाहिए। एक तारीख को, दोनों प्रकार के कपास का बिक्री मूल्य स्वाभाविक रूप से समान होना चाहिए, अन्यथा उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए कोई बाजार नहीं होगा। अनुसूची 'डी' में दोनों वस्तुओं के इस बिक्री मूल्य पर कर लगाया गया है।

- 27) ऐसा लगता है कि पूरा भ्रम इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि स्थानीय कपास के संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि कर पहले खरीद मूल्य पर लगाया जाएगा न कि पहली बिक्री मूल्य पर जैसा कि आयातित कपास के मामले में होता है। लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि स्थानीय कपास के मामले में, जाहिर है, विक्रेता का पहला खरीद मूल्य उत्पादक के पहले बिक्री मूल्य के समान होता है। नतीजतन, दोनों ही मामलों में कर पहली बिक्री कीमत पर होगा। स्थानीय कपास के संबंध में पहले खरीद मूल्य का उल्लेख करने का कारण यह था कि विधायिका स्थानीय उत्पादक, अर्थात् किसान पर कर नहीं लगाना चाहती थी। यदि उनके मामले में भी बिक्री मूल्य पर कर लगाया गया होता, तो उन्हें नियमित खाते रखने और खजाने में कर जमा करने की आवश्यकता होती और ऐसा प्रतीत होता है कि वे इससे बचना चाहते थे।
- 28) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि फर्म ए. टी. बी. मेहताब माजिद और कंपनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है, और इसलिए, उसे उस आधार पर सफल होना चाहिए। उनका तर्क है, 'आयातित खाल और खाल' के लिए 'आयातित कपास' और 'स्थानीय खाल और खाल' के लिए 'स्थानीय कपास'। यदि ऐसा किया जाता है, तो उनका कहना है कि परिणाम वही होगा जो फर्म ए. टी. बी. मेहताब माजिद एंड कंपनी के मामले में था। हालांकि यह तर्क आकर्षक है, लेकिन इसकी जांच नहीं की जा सकती है। ए. हाजी अब्दुल शुकूर एंड कंपनी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप्स ने फैसला किया कि 'कच्ची खाल और खाल' और 'टैन की खाल और खाल' दो अलग-अलग वस्तुएं हैं। अनुच्छेद 304 (ए) द्वारा निषिद्ध भेदभाव केवल समान वस्तुओं के बीच है न कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच। यह स्वयंसिद्ध है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) को ध्यान में रखते हुए, समान वस्तुओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, भले ही वे स्थानीय रूप से उत्पादित हों या आयातित हों। कर का बोझ समान होना चाहिए। फर्म ए. टी. बी. मेहताब माजिद एंड कंपनी के मामले में, इसी तरह के सामानों के साथ भेदभाव किया गया था, अर्थात् 'स्थानीय रूप से उत्पादित टिन की खाल और खाल' और 'टैन की खाल और खाल का आयात किया गया था'; और इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय के फैसले के निहितार्थ को समझने के लिए, मद्रास नियम को उद्धृत करना उचित होगा:—

"16. (1) बिना कपड़े की खाल और/या खाल के मामले में धारा 3 (1) के तहत कर उस विक्रेता से लगाया जाएगा जो राज्य में अंतिम खरीदार है, जिसे धारा 3 (3) के तहत उस राशि पर कराधान से छूट नहीं है जिसके लिए वे उसके द्वारा खरीदे गए हैं।

(2) (i) उन खालों या खालों के मामले में जिन्हें राज्यों के बाहर टैन किया गया है, धारा 3 (1) के अधीन कर उस विक्रेता से लगाया जाएगा जो राज्य में पहला विक्रेता है, ऐसी खालों या खालों में जो उस राशि पर धारा 3 (3) के अधीन कराधान से मुक्त नहीं है जिसके लिए वे उसके द्वारा बेचे जाते हैं।

(ii) राज्य के भीतर टैन की गई खाल या खाल के मामले में, धारा 3 (1) के तहत कर उस व्यक्ति से लगाया जाएगा जो ऐसी खाल या खाल का पहला विक्रेता है जिसे उसके द्वारा बेची गई राशि पर धारा 3 (3) के तहत कराधान से छूट नहीं दी गई है: बशर्ते कि, यदि वह यह साबित करता है कि कर पहले से ही उप-नियम (1) के तहत उन टैन की खाल और खाल पर लगाया जा चुका है, जिनमें से टैन की खाल और खाल का उत्पादन किया गया था, तो वह ऐसा उत्तरदायी नहीं होगा।

(3) यह साबित करने का भार कि कोई लेन-देन इस नियम के तहत कराधान के लिए उत्तरदायी नहीं है, विक्रेता पर होगा।

29) इस नियम के तहत, कच्ची खाल या खाल के मामले में, अंतिम खरीदार खरीद मूल्य पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। उप-नियम (2) के अनुसार आयातित के साथ-साथ स्थानीय तैलीय खाल और खाल पर पहली बिक्री पर कर लगाया जाता है। यदि नियम परंतुक को छोड़ देता, तो कोई परेशानी पैदा नहीं होती, क्योंकि आयातित और स्थानीय टैन की खाल और खाल के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन इस नियम का प्रावधान भेदभाव की बुराई लाता है। यदि राज्य के भीतर खाल और खाल को टैन किया जाता है और उन पर उपनियम (1) के तहत कर लगाया जाता है तो राज्य में खाल और खाल पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। यह इस प्रकार है कि 'आयातित टैन की खाल और खाल' और 'राज्य के भीतर संसाधित टैन की खाल और खाल' के बीच भेदभाव हुआ। यदि कोई व्यक्ति आयातित चमड़े की खाल और खाल का सौदा करता है, तो उसे बिक्री-कर का भुगतान करना पड़ता है। यदि वह कच्ची खाल और खाल भी खरीदता है और फिर उन्हें बिक्री के लिए टैन कराता है, तो वह केवल कच्ची खाल और खाल के खरीद मूल्य पर खरीद-कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और टैन की खाल और खाल पर कोई कर नहीं लगेगा। यह भेदभाव था, जो परंतुक द्वारा लाया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। जहाँ तक 'कपास' का संबंध है, हरियाणा अधिनियम में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हरियाणा अधिनियम के तहत, राज्य में पहली बिक्री मूल्य पर आयातित और स्थानीय कपास दोनों पर कर लगाया जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विवादित प्रावधान के अधिकारों पर हमला उचित नहीं है।

30) एकमात्र अन्य विवाद, जो अब तक अनसुलझा रहा है, वह यह है कि क्या निर्धारिती को उन आकलनों को फिर से खोलने का विकल्प दिया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से प्रभावित थे, जो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15 के अनुरूप नहीं थे। पहले उदाहरण में, यह एक सक्षम प्रावधान है। विभाग के पास प्रत्येक मूल्यांकन को फिर से नहीं खोलने का कोई विकल्प नहीं है जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है। वे, कानून के तहत, मूल्यांकन को फिर से खोलेंगे। विकल्प केवल निर्धारिती के लिए है और पूरी तरह से उसके लाभ के लिए है। वह मूल्यांकन को फिर से खोलने से मना कर सकता है, जिस क्षण उस ओर से उसे एक नोटिस दिया जाता है, यह कहकर कि वह नहीं चाहता कि इसे फिर से खोला जाए। ऐसा प्रावधान, जो केवल निर्धारिती का पक्ष लेता है, उसे किसी भी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता है। हम इस विवाद में कोई ताकत नहीं देखते हैं और इसे पीछे हटा दिया जाता है।

31) इसलिए, शुद्ध परिणाम यह है कि तीसरे विवाद में कोई बल नहीं है और इसे विफल होना चाहिए।

- 32) यह विवाद अब मद्रास राज्य बनाम एन. के. नटरफा मुदलियार (26) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से समाप्त होता है उच्चतम न्यायालय ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम संयुक्त वाणिज्यिक टैग अधिकारी में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया है। ईस्ट इंडिया सैंडल ऑयल डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में मद्रास के निर्णय पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी गई है।
- 33) मामले के इस दृष्टिकोण में, यह विवाद भी विफल हो जाता है।
- 34) ऊपर दर्ज कारणों से, यह याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है; लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

प्रेम चंद पैनडिट, जे. -मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नूह, हरियाणा